



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042025-262197
CG-DL-E-02042025-262197

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, रविवार, मार्च 30, 2025/ चैत्र 9, 1947

No. 105]

NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 30, 2025/ CHAITRA 9, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च 2025

मामला सं. एडी (ओआई) – 03/2025

विषय : ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो ऐश मेटलर्जिकल कोक" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

1. फा. सं. 6/03/2025- डीजीटीआर.—इंडियन मेटलर्जिकल कोक मैनुफक्चर्स एसोसिएशन ('आईएमकॉम') (जिसे इसके बाद "आवेदक" के रूप में कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी ("प्राधिकारी") के समक्ष यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ("सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम") और यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 ("पाटनरोधी नियमावली") के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस ("संबद्ध देश") से आयातित अथवा निर्यातित "लो ऐश मेटलर्जिकल कोक" ("संबद्ध वस्तुएं" अथवा "विचाराधीन उत्पाद") के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "लो ऐश मेटलर्जिकल कोक" है, अर्थात् मेटलर्जिकल कोक, जिसमें राख की मात्रा 18% से कम है, जिसमें अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक शामिल नहीं है जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा 0.030% तक है, जिसका आकार 30 मि.मी. तक है और फेरोअलॉय निर्माण में उपयोग के लिए 5% तक साइज टोलरेंस है। मेटलर्जिकल कोक का उपयोग ऐसे उद्योगों में, जहां भट्टों या भट्टियों में एक समान और उच्च तापमान आवश्यक होता है, जैसे कि पिग आयरन, फाउंड्री, फेरो अलॉय, रासायनिक संयंत्रों और इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में, प्राथमिक ईंधन के रूप में किया जाता है।
4. मेट कोक को उच्च तापमान (1100 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच) पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति/ नियंत्रित उपस्थिति में कोकिंग कोयले के विनाशकारी डिस्टिलेशन द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिससे कोयला नरम होकर तरल हो जाता है और उसके बाद कठोर लेकिन छिद्रयुक्त पिंडों में फिर से जम जाता है। मेट कोक कुछ खनिज और अवशिष्ट वाष्पशील पदार्थों के साथ कार्बन का एक रूप होता है।
5. विचाराधीन उत्पाद को सामान्य तौर पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के एचएस कोड 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 और 2704 0090 के अंतर्गत भारत में आयात किया जाता है। तथापि, यह संभव है कि संबद्ध वस्तुओं को अन्य शीर्षों के अंतर्गत भी आयात किया जा सकता है और इसीलिए, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। पाटन और क्षति विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए उपरोक्त टैरिफ कोड के लिए डीजी सिस्टम डेटाबेस से आयातों के संबंध में डेटा का मूल्यांकन किया गया है।
6. संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियां और साथ ही पीसीएन के निर्माण के लिए अपने प्रस्ताव, यदि कोई हो, प्रदान कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. आवेदकों ने यह दावा किया है कि भारत में पाटित की गई संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। दोनों उत्पादों की तकनीकी विशिष्टताओं, कार्यों और अंतिम उपयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों प्रथम दृष्टया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी का यह मानना है कि दोनों को पाटनरोधी नियमावली के तहत "समान वस्तु" के रूप में माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तुएं मानी जा रही हैं।

ग. संबद्ध देश

8. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस हैं।

घ. जांच की अवधि

9. प्राधिकारी ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से 31 सितंबर, 2024 (12 माह) की अवधि को जांच की अवधि, अर्थात् पीओआई के रूप में माना है। क्षति की अवधि में दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 और जांच की अवधि शामिल है।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

10. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से इंडियन मेटलर्जिकल कोक मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ('आईएमकॉम') द्वारा दायर किया गया है। आईएमकॉम के निम्नलिखित सदस्यों ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए अपने आंकड़े दाखिल किए हैं।
- क. भाटिया कोक एंड एनर्जी लिमिटेड (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड),
 - ख. बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड,
 - ग. जिंदल कोक लिमिटेड
 - घ. पवनपुत्र ईकोक प्राइवेट लिमिटेड,
 - ड. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड,
 - च. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड
 - छ. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड, और
 - ज. वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड
11. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि भारत में, मेट कोक को या तो इस्पात के विनिर्माण की प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती के रूप में उत्पादित किया जाता है या उसकी वाणिज्यिक बाजार में बिक्री की जाती है या आंशिक रूप से बिक्री के लिए और आंशिक रूप से कैप्टिव खपत के लिए उत्पादित किया जाता है। उत्पाद के कम से कम 19 उत्पादक हैं जो कैप्टिव रूप से मेट कोक का उत्पादन करते हैं। तथापि, ऐसे उत्पादकों को वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के दायरे का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित कारणों से मेट कोक के उत्पादकों के रूप में नहीं माना गया है।
- क. इस्पात निर्माण के एक भाग के रूप में मेट कोक के विनिर्माण में लगे उत्पादक इसे एक उत्पाद के रूप में मान्यता नहीं देते हैं।
 - ख. यह केवल इस्पात के उत्पादन के लिए इन उत्पादकों द्वारा अपेक्षित एक इनपुट है और इस तरह की उत्पादन प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती है।
 - ग. इस्पात उत्पादकों की वेबसाइटों में मेट कोक को "उत्पाद" के रूप में नहीं बताया गया है।
 - घ. इस्पात विनिर्माता मेट कोक बाजार में आयातकों अथवा घरेलू उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं।
 - ड. कैप्टिव उत्पादकों को मेट कोक बाजार की स्थितियों से अलग रखा जाता है।
 - च. इस्पात विनिर्माता वास्तव में संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माता न होकर उपभोक्ता हैं।
 - छ. मेट कोक इन उत्पादकों के लिए कच्ची सामग्री है, न कि यह बिक्री के लिए बनाया गया उत्पाद है।
12. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के प्रावधान में दो या अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों में अलग-अलग उद्योग पर विचार करने की अनुमति है और प्रत्येक उद्योग के उत्पादकों में अलग-अलग उद्योग शामिल होते हैं। प्राधिकारी ने मर्चेन्ट मार्केट और कैप्टिव मार्केट को अलग-अलग प्रतिस्पर्धी बाजार माना है और इनमें से प्रत्येक बाजार के उत्पादकों को अलग-अलग उद्योग माना गया है।
13. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि कुछ घरेलू उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और इस प्रकार, इसे घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाना चाहिए। प्राधिकारी ने सभी घरेलू उत्पादकों को पत्र जारी किए और उत्पादन, क्षमता, बिक्री, कैप्टिव खपत और आयात (स्व-आयात और संबंधित पक्षों द्वारा) के बारे में विवरण की मांग की है। जिन उत्पादकों ने उत्तर दिया है, उनके लिए वास्तविक सूचना पर विचार किया गया है। उत्पादकों के उत्पादन की तुलना में आयातों की मात्रा के आधार पर, प्राधिकारी ने केवल

निम्नलिखित उत्पादकों को स्टैंडिंग के प्रयोजन के लिए कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण के लिए अयोग्य माना है।

- क. महालक्ष्मी एन्नोर कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
- ख. महालक्ष्मी वेलमैन फ्यूल्स एलएलपी
- ग. मदरसन कंसोलिडेट
- घ. श्री अरिहंत ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
- ङ. श्री इलेक्ट्रोमेल्ट्स लिमिटेड
- च. वीजा कोक लिमिटेड

14. निम्नलिखित उत्पादकों ने प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर दिया है और एसोसिएशन द्वारा दायर किए गए आवेदन का समर्थन किया है।

- क. कार्बन एज इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ख. कोरोमंडल मेट कोक इंडस्ट्रीज
- ग. नारायणी कोक प्राइवेट लिमिटेड
- घ. नीलांचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड
- ङ. तिरुपति ट्रेडर्स
- च. वराह वेंचर्स (गिरधारी कोक)
- छ. हर्ष फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
- ज. तमिलनाडु कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
- झ. उषा फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
- ञ. बंगाल एनर्जी लिमिटेड

15. आवेदक घरेलू उत्पादक के पास पात्र भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। समर्थकों के साथ ही, आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल पात्र भारतीय उत्पादन में 85% हिस्सा शामिल है। आवेदक घरेलू उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी निर्यातक अथवा भारत में पाटित वस्तुओं के आयातक से संबद्ध नहीं हैं। इस प्रकार, आवेदक घरेलू उत्पादकों के पास भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इस प्रकार, आवेदक घरेलू उत्पादक नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग में आते हैं और यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार आधार की आवश्यकता को पूरा करता है।

कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

- क) चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदकों ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए, चीन के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। पैरा 7 के तहत, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत के आधार पर अथवा भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर किया जाना आवश्यक है।
17. जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय को उचित रूप से समायोजित किया गया है।

ख) अन्य संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य

आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि वे अन्य देशों में समान उत्पाद के लिए तुलनात्मक कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे, स्थानीय बाजार में बिक्रियों के लिए कीमत सूची अथवा वाणिज्यिक इनवॉयस व्यावसायिक रूप से संवेदनशील और गोपनीय प्रकृति के थे। उसी को देखते हुए, आवेदक ने घरेलू उद्योग के उपभोग मानदंडों के आधार पर संबंधित देशों में विनिर्माण की प्रतिनिधित्व लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के साथ विधिवत समायोजित किया गया है।

निर्यात कीमत

18. आवेदक ने बाजार आसूचना के अनुसार भारत में आयातों के अनुसार सूचित की गई सीआईएफ कीमत को अपनाया है। आवेदकों द्वारा प्रदान की गई सूचना की तुलना डीजी सिस्टम डेटा से की गई है। प्रथम दृष्टया आकलन करने के प्रयोजन के लिए, कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का पता लगाने के लिए डीजी सिस्टम से डेटा को अपनाया गया है। कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए, कीमत को समुद्री माल भाड़ा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, बंदरगाह व्यय, बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, वस्तुसूची परिवहन की लागत और क्रेडिट लागत के साथ समायोजित किया गया है। जांच शुरूआत करने के लिए निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटन मार्जिन

19. ऊपर उल्लिखित किए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क (1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। यह देखने में आया है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

च. क्षति और कारणात्मक संबंध

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने आयात की गई वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि के रूप में कथित पाटन होने के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जो भारत में उत्पादन अथवा खपत, कीमत में कटौती और घरेलू उद्योग पर मूल्य ह्रास प्रभाव के संबंध में है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल, बाजार अंश के संबंध में इसके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं का पाटन होने से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

21. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि आयातों के कारण से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

22. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, जो कि उक्त देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध से संबंधित है और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के साथ-साथ पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी, उपरोक्त देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जांच की शुरुआत करते हैं तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. प्रक्रिया

23. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 के तहत बताए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा।

झ. सूचना की प्रस्तुति

24. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विवरणात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएसवर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल फॉर्मेट में हों। फाइलों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

25. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों और भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप और तरीके से सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच के संबंध में अपने अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप और तरीके से कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

ब. समय सीमा

27. वर्तमान जांच के संबंध में कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित ईमेल पत्तों dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए जिस दिन इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार प्रेषित किया गया था। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए मांग करने वाली सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।
29. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण को प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ट. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसके साथ-साथ उसका एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।
31. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने होंगे। यदि अनुरोध कई भागों में किया जाता है, तो यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक भाग में एक सूचीबद्ध तालिका प्रदान करें, जिसमें सभी भागों/ ईमेल और संलग्न दस्तावेजों की सामग्री को उल्लिखित किया जाता है। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ संख्या सुनिश्चित की जाए।
32. जहां मूल दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ सही अनुदित पाठ प्रदान किया जाए।
33. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। इस तरह का अंकन किए बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
34. अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा खाली रखा गया हो (यदि सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और उस सूचना के आधार पर सारांश दिया गया हो जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश में अगोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय

सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सारांश करना संभव नहीं होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों का अगोपनीय पाठ प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर, दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

35. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच किए जाने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसका प्रकटीकरण करने को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
36. गोपनीयता के दावों पर उचित कारण के विवरण के लिए इसके सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।
37. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना के संगत पैरा के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
38. प्राधिकारी इस पर संतुष्ट होने और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ठ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। प्रश्नावली उत्तर अथवा अन्य अनुरोध का गोपनीय पाठ अधिमानतः उसी दिन सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए और वह किसी भी मामले में गोपनीय आधार पर अनुरोध दाखिल करने के अगले दिन से बाद में नहीं किया जाना चाहिए। अनुरोधों/ उत्तरों/ सूचना के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने में विफलता के कारण हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना जा सकता है।

ड. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त समय अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, 29 March 2025

Case No. AD(OI) -03/2025

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of “Low Ash Metallurgical Coke” originating in or exported from Australia, China, Colombia, Indonesia, Japan and Russia.

1. **F.No. 6/03/2025-DGTR.**—Indian Metallurgical Coke Manufacturer’s Association (‘IMCOM’) (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application on behalf of the domestic industry before the Designated Authority (“**Authority**”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended (“**Customs Tariff Act**”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended (“**AD Rules**”), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Low Ash Metallurgical Coke” (“**subject goods**” or “**product under consideration**”) originating in or exported Australia, China, Colombia, Indonesia, Japan and Russia (“**subject countries**”).
2. The applicants have alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating or exported from the subject countries and have requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present investigation is Low Ash Metallurgical Coke that is, Metallurgical Coke having ash content below 18% excluding ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing. Metallurgical Coke is used as a primary fuel in industries where a uniform and high temperature is required in kilns or furnaces, such as in production of pig iron, foundries, ferro alloys, chemical plants and steel plants.
4. Met Coke is produced by destructive distillation of coking coal in the absence/regulated presence of oxygen at high temperatures (ranging between 1100 to 1350 degree centigrade) causing the coal to soften, liquefy and then re-solidify into hard but porous lumps. Met Coke is a form of carbon along with some mineral and residual volatile material.
5. The PUC is generally imported into India under HS Codes 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030, and 2704 0090 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. However, it is possible that the subject goods may also be imported under other headings and therefore, the Customs tariff heading is indicative only and is not binding on the scope of the product. Import data from the DG Systems database has been assessed for the above tariff codes for the purposes of dumping and injury analyses.
6. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC as well as their proposal for their construction of PCNs, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

7. The applicants have claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the technical specifications, functions and end-use of the two products. The Authority notes that the two are *prima facie* technically and commercially substitutable. Hence, for the purposes of the present investigation, the Authority holds that the two should be treated as “like article” under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as ‘like articles’ to the subject goods being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRIES

8. The subject countries in the present petition are Australia, China, Colombia, Indonesia, Japan and Russia.

D. PERIOD OF INVESTIGATION

9. The Authority has considered the period from October 1, 2023 – September 31, 2024 (12 Months) as the period of investigation, i.e., the POI. The period of injury covers the periods from April 1, 2021 to March 31, 2022, April 1, 2022 to March 31, 2023, April 1, 2023 – March 31, 2024, and the POI.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

10. The application has been filed by Indian Metallurgical Coke Manufacturer’s Association (‘IMCOM’) on behalf of the domestic industry. The following members of the IMCOM have filed their data for the purpose of the present investigation.
- Bhatia Coke and Energy Limited (Aquaterra Coke & Energy Limited),
 - BLA Coke Private Limited,
 - Jindal Coke Limited
 - Pawanputra ECoke Private Limited,
 - Saurashtra Fuels Private Limited,
 - SU Mangala Coke Private Limited
 - United Coke Private Limited, and
 - Vedanta MALCO Energy Limited
11. The applicant has submitted that in India, met coke is either produced as an intermediate in the manufacturing process of steel or is sold in the merchant market or is partly produced for sale and partly for captive consumption. There are at least 19 producers of the product producing met coke captively. However, such producers have not been considered as producers of met coke for determination of scope of the domestic industry in the present investigation, for the following reasons.
- Producers engaged in manufacturing met coke as a part of steel making do not recognize it as a product.
 - It is only an input required by these producers for production of steel and is an intermediate in such production process.
 - Websites of the steel producers do not report met coke as a “product”.
 - The steel manufacturers do not compete in the met coke market either with imports or

- with domestic producers.
- e. The captive producers are insulated from the market situations in the met coke market.
 - f. The steel manufacturers are actually consumers of the subject goods, rather than manufacturers of the same.
 - g. Met coke is a raw material for these producers and not a product meant for sale.
12. The proviso to Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules allows for considering separate industry in two or more competitive markets and the producers within each industry comprise of separate industries. The Authority has considered merchant market and captive market as separate competitive markets and producers within each of these markets have been considered to constitute separate industry.
13. The domestic industry has submitted that some of the domestic producers have imported the product under consideration, and thus, should not be considered as part of domestic industry. The Authority issued letters to all domestic producers and sought details regarding production, capacity, sales, captive consumption and imports (self-imports and by related parties). Actual information has been considered for the producers which have furnished a response. Based on the volume of imports compared with the production of the producers, the Authority has considered only the following producers ineligible for determination of total Indian production for the purpose of standing.
- a. Mahalakshmi Ennore Coke and Power Private Limited
 - b. Mahalakshmi Wellman Fuels LLP
 - c. Motherson Consolidate
 - d. Shree Arihant Trade Links Private Limited
 - e. Shri Electromelts Limited
 - f. Visa Coke Limited
14. The following producers have furnished response to the letter sent by the Authority and have supported the application filed by the association.
- a. Carbon Edge Industries Limited
 - b. Coromandel Met Coke Industries
 - c. Narayani Coke Private Limited
 - d. Neelanchal Carbo Metalicks Limited
 - e. Tirupati Traders
 - f. Varah Ventures (Girdhari Coke)
 - g. Harsh Fuels Pvt. Ltd
 - h. Tamil Nadu Coke & Power Private Limited
 - i. Usha Fuels Private Limited
 - j. Bengal Energy Limited
15. The applicant domestic producers constitute a major proportion of the eligible Indian production. Along with the supporters, the applicant domestic producers constitute 85% of the total eligible Indian production. The applicant domestic producers have not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation and are not related

to any of the exporters of the subject goods in the subject countries or importers of the dumped articles in India. Thus, the applicant domestic producers constitute a major proportion of the total domestic production of like article in India. Thus, the applicant domestic producers constitute domestic industry under Rule 2(b), and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

BASIS OF ALLEGED DUMPING

NORMAL VALUE

a) Normal value for China PR

16. The applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and therefore, the Chinese producers should be called upon to show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the production and sale of that product under consideration. Unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure – I to the AD Rules. Under Para 7, normal value for a non-market economy country is required to be determined on the basis of prices of subject goods in the market economy third country or price from such third country to other countries, including India, or on some other reasonable basis including the price paid or payable in India.
17. The normal value, for the purpose of initiation of the investigation, has been constructed based on the cost of production of the domestic industry of the subject goods, after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

b) Normal value for other subject countries

The applicants have submitted that it was not able to obtain comparable prices for like product in other countries, the price lists or commercial invoices for sales in the local market being commercially sensitive and confidential in nature. In view of the same, the applicant has constructed the normal value based on the representation cost of manufacturing in the respective countries based on the consumption norms of the domestic industry, duly adjusted with the selling, general, and administrative expenses and reasonable profit.

EXPORT PRICE

18. The applicant has adopted the CIF price reported as per imports into India as per market intelligence. The information provided by the applicants has been compared with the DG Systems data. For the purpose of the *prima facie* assessment, DG systems data has been adopted for ascertaining ex-factory export price. To determine the ex-factory export price, the price has been adjusted with ocean freight, inland freight, port expenses, insurance, commission, bank charges, inventory carrying cost and credit cost. There is sufficient *prima facie* evidence with respect to export price to justify the initiation of the investigation.

DUMPING MARGIN

19. Considering the normal value and export price as elaborated above, the dumping margin has been determined, in accordance with Section 9A(1)(a) of the Customs Tariff Act. It is seen that the dumping margin is not only above the *de minimis* levels, but also significant.

F. INJURY AND CAUSAL LINK

20. The information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury suffered as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production or consumption in India, price undercutting and price depressing effect on the domestic industry. The performance of the applicants has been adversely impacted in respect of profitability, return on investment, market share as a result of the increase in imports of the PUC at an injurious price for the domestic industry. There is sufficient *prima facie* evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject countries.
21. The applicants have also claimed that the imports are causing material injury to the domestic industry.

G. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

22. On the basis of duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry pertaining to dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. PROCEDURE

23. Principles, as stated under Rule 6 of the AD Rules, shall be followed in the present investigation.

I. SUBMISSION OF INFORMATION

24. All the communications should be sent to the Designated Authority via email at email address dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format. Submissions requiring special software to access the files will not be accepted.
25. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

J. TIME LIMIT

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
29. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

K. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS

30. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the AD Rules. Failure to adhere to the above may lead to the rejection of the response / submissions.
31. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately. In case, the submission is made in multiple parts, it is instructed to provide an index table in each part outlining the contents of all parts/emails and documents enclosed. Please ensure page numbering on all submissions.
32. Where the original documents are in a language other than Hindi and English, the interested parties are requested to ensure that the true translated version is provided along with the original documents.
33. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties may offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-

confidential version of the documents.

35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of relevant paragraphs of this initiation notification.
38. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

L. INSPECTION OF PUBLIC FILE

39. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. The non-confidential version of the questionnaire response or other submissions should preferably be circulated to all other interested parties on the same day and, in no case, later than the day following the filing of submissions on a confidential basis. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

M. NON-COOPERATION

40. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Darpan Jain, Designated Authority